IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय सुरक्षा–क्षेत्र में सुधार

रश्मि बाजपेयी
शोध छात्रा,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सारांश

भारत और पाकिस्तान का विभाजन "द्वि–राष्ट्र सिद्धांत"पर आधारित था। तब से पाकिस्तान हमारा स्वाभाविक शत्रु बन गया और हमारी रक्षा नीतियां पाकिस्तान के सम्बन्ध में बनाई गईं। चीन की पीएलए के खिलाफ 1962 के युद्ध की पराजय के बाद,नीति निर्माताओं को हमारे दो निकटतम पड़ोसियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए रक्षा क्षेत्र में आवश्यक सुधार लाने का एहसास हुआ। हमारे देश में सुधारों की गति धीमी गति से चल रही है, जिसने हमें विभिन्न जटिल सुरक्षा खतरों से अवगत कराया है। यह लेख 2014 के बाद रक्षा सुधारों के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। सुधारों के रास्ते में आने वाली मुख्य चिंताओं पर भी गौर करने का प्रयास किया गया है और मुद्दों को हल करने के लिए कई उपाय दिए गए हैं।

मुख्य शब्दः सुरक्षा क्षेत्र, सुधार, स्त्रातेजिक, आत्मनिर्भरता, नवाचार।

परिचय

पिछले 70 वर्षों से अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन और उनके चीफ ऑफ स्टाफ इस्माय द्वारा पारित उच्च रक्षा संगठन की वसीयत अपरिवर्तित बनी हुई है। जबकि हमारे राजनीतिक नेता और अभिजात वर्ग देशों के समुदाय में भारत को एक "महान शक्ति"के रूप में देखते हैं,लेकिन इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए उनके प्रयास अपर्याप्त हैं। आजादी के प्रारंभिक वर्षों में सुरक्षा तंत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया क्योंकि तत्कालीन नेहरू प्रशासन ने इसे सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की देखभाल करने में सक्षम माना था।

आज़ादी के तुरंत बाद हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमारे निकटतम पड़ोसियों यानी पाकिस्तान और चीन द्वारा हमला किया गया। पंडित नेहरू के शासनकाल में हमारी रक्षा तैयारी केवल पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित थी। चीन द्वारा उत्पन्न खतरे को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया और हमने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। अपने संबंधों को और भी अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने "हिंदी चीनी भाई–भाई" की भावना के साथ काम किया।

लेकिन हमें आश्चर्य हुआ जब चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया और 1962 के युद्ध में चीन के खिलाफ मिली हार ने कई मोर्चों पर हमारे सुरक्षा तंत्र की पोल खोल दी। यह वह समय था जब हमारे सशस्त्र बलों की दक्षता पर सवाल उठाए गए थे। आलोचनाओं का खुले दिल से स्वागत किया गया और सरकार ने हमारी रक्षा नीति में मुख्य चिंताओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया,जिससे रक्षा क्षेत्र में सुधार हुए।

चीन के खिलाफ 1962 के युद्ध में मिले झटके से पाकिस्तान को फायदा हुआ और हमने 1965, 1971 और 1999 में उनके साथ युद्ध लड़े। बाद के सभी युद्ध पिछले संघर्षों से सीखे गए सबक का उपयोग करके लड़े गए। इस बीच,हमारे द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के सभी पहलुओं की जांच के लिए कई सुधार समितियां गठित की गईं। रक्षा सुधार अंतर्निहित हितों और नौकरशाही प्रतिद्वंदिता के कारण जटिल हैं, हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में प्रारंभिक परिवर्तन लाने में कठिनाई हुई। दशकों से रिपोर्टों ने हमारी सैन्य संरचना और प्रक्रियाओं में अंतर्निहित मूलभूत अक्षमताओं का खुलासा किया है,लेकिन जब निर्णय लेने की बात आई तो यथास्थिति बनाए रखी गई।

2014 के बाद रक्षा सुधारः मोदी युग

भारत,दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे युवा लोकतंत्र, परमाणु युद्ध से लेकर गैर–पारंपरिक युद्ध तक,सबसे जटिल खतरों और चुनौतियों का सामना करता है। अफ़ग़ानिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान–पाकिस्तान सीमा पर निरंतर संघर्ष,भारत और चीन के बीच अस्थिर सीमा विवाद,और पूरे रणनीतिक परिदृश्य में कट्टरपंथी उग्रवाद का बढ़ता कदम दक्षिण एशिया में प्रमुख भू–रणनीतिक चुनौतियाँ हैं। वामपंथी उग्रवाद के उदय और शहरी आतंकवाद के बढ़ते खतरे ने भारत की सुरक्षा स्थिति को नाटकीय रूप से नुकसान पहुंचाया है। हमारे देश की सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दे समय के साथ नाटकीय रूप से विकसित हुए हैं।

2009 में, भारत को सिरपर खड़ी रहने वाले दो मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पहली, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी हमलों का खतरा, और दूसरी, चीन के साथ सीमा विवाद और उसके साथ हो रहे तनाव का सामना करना। इस समय, भारत की सुरक्षा में सुधार के लिए उच्च स्तरीय बैठकें और रक्षा योजनाएं शुरू की गईं थीं, ताकि देश इसे सफलता से पार कर सके। इसके बाद के वर्षों में भी, इस समायोजन को बनाए रखने के लिए नई रक्षा नीतियों और कदमों की घोषणा की गई है ताकि भारत अपने बचाव और सुरक्षा परिस्थितियों का समर्थन कर सके।

पहले, सैन्य सुधारों की गति धीमी और कठिन थी, लेकिन जैसे–जैसे सुरक्षा रणनीतियाँ अधिक जटिल होती गईं, भारत ने अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में बदलाव किया है। यह परिवर्तन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले प्रशासन के सत्ता संभालने के बाद से देखा जा रहा है। सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में लाइसेंसिंग, डीरेग्यूलेशन, निर्यात प्रोत्साहन और विदेशी निवेश उदारीकरण सहित कई पहल लागू की गई हैं। पीएम मोदी खुलेपन, पूर्वानुमेयता और व्यापार करने में आसानी पर जोर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

निम्न सूचीबद्ध परिवर्तन हमारे सैनिकों को भविष्य बनाने के लिए आवश्यक दृढ़ता और समर्पण को प्रदर्शित करते हैं –

भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति

कारगिल पर समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय सेना के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति की वकालत की। दो दशक से अधिक समय के बाद भारत में सीडीएस की नियुक्ति की गई,जिससे वह रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के शीर्ष सैन्य सलाहकार बन गए। जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी, 2020 को भारत के पहले सीडीएस बने।

सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) की स्थापना

1 जनवरी, 2020 को नागरिक–सैन्य एकीकरण की सुविधा के लिए सैन्य मामलों के विभाग की स्थापना की गई थी। सीडीएस डीएमए सचिव होंगे। समय पर संचालन सुनिश्चित करने के लिए,लगभग 170 नागरिक भूमिकाओं को तुरंत डीएमए में स्थानांतरित कर दिया गया। अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव और अन्य सशस्त्र बल अधिकारियों को त्वरित कामकाज की गारंटी देने का काम सौंपा गया

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अनुरूप, मेक इन इंडिया अभियान को रक्षा क्षेत्र द्वारा जोरदार बढ़ावा दिया गया। अगस्त 2020 में रक्षा उपकरण आयात को निलंबित कर दिया गया था। स्वचालित दृष्टिकोण के माध्यम से 74ः तक एफडीआई की अनुमति दी गई थी,और सरकार (अनुमोदित) मार्ग के माध्यम से 74ः से अधिक की अनुमति दी गई थी। भारत का इरादा विश्वव्यापी रक्षा उपकरण उत्पादन केंद्र बनने का है। घरेलू विक्रेताओं को 2020 में सभी रक्षा अधिग्रहण स्वीकृतियों में से 87ः प्राप्त हुईं। सितंबर 2020 में,घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस को बढ़ावा देने के लिए नए डीएपी को अधिकृत किया गया था। 2020–21 में बजट स्थानीय स्तर पर निर्मित रक्षा उपकरणों के लिए 52,000 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। इसके अलावा,भारत में नई प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक असाधारण प्रयास को प्रोत्साहित किया गयाः भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने मई 2020 में ब्टप्क–19 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिकॉर्ड समय में भारतीय वेंटिलेटर का निर्माण किया। नवंबर 2020 में, घरेलू स्तर पर निर्मित और निर्मित क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (फत्ै।ड) ने मध्यम दूरी और मध्यम ऊंचाई पर लक्ष्य पर हमला किया। पिनाका रॉकेट प्रणाली, जिसकी कल्पना और उत्पादन इंडोनेशिया में किया गया था, ने नवंबर 2020 में 45–60 किमी की रेंज का परीक्षण पास किया।

संभावित सैन्य प्रगति के लिए एक मंच के रूप में सितंबर 2020 में IdeÛ4Fauji का परिचय रक्षा मंत्रालय में डिजिटल इंडियारू डवक ने सुविधाओं का उपयोग किया डिजिटल इंडिया से डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से रक्षा उद्योग को वैध बनाना और सुधारना।

निम्नलिखित पहल लागू की गई

सुरक्षा जोखिमों का मुकाबला करने के लिए MoD LAN के पास एक नई साइबर सुरक्षा नीति है। रक्षा मंत्रालय के पेंशन प्रावधान को ऑनलाइन कर दिया गया है। छावनी सेवाएँ और कैंटीन आउटलेट अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अगस्त 2020 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की पहली डिजिटल सुनवाई हुई। 17.5 लाख एकड़ रक्षा संपत्ति के साथ रक्षा संपदा जीआईएस–आधारित प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गई। एनसीसी मोबाइल ऐप अगस्त 2020 में उपलब्ध होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत ने दिसंबर 2020 तक 65 ऑनलाइन शिविरों की मेजबानी की, जिसमें 5700 कैडेटों ने भाग लिया।

रक्षा अधिग्रहण में दृश्यता के साथ गति का एक आधुनिक युग

2020 के दशक में पिछले दस वर्षों में आधुनिकीकरण की दिशा में सबसे आक्रामक धक्का देखा गया। पिछले वर्ष के विपरीत, 2020– 21 के लिए आवंटित बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सितंबर 2020 में, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को अधिकृत किया गया था। एमएसएमई को 100 करोड़ रुपये तक की खरीद आवंटित की गई है। संशोधित और सरलीकृत परीक्षण और परीक्षण; स्टार्टअप क्षेत्र के बढ़ने और विशेष रक्षा कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ने के कारण परीक्षण का खर्च और अवधि कम हो गई है। अक्टूबर से डीएपी 2020 में तीसरे पक्ष के परीक्षण की अतिरिक्त अनुमति दी गई थी, जिसमें वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए) या गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) या मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष की परीक्षण एजेंसियों के पास जाने का विकल्प था। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना भी बनाई, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्ट–अप को प्रोत्साहित करना और समर्थन करना है।

अधिक समृद्धि और सुरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों को पाटना

अक्टूबर 2020 में, 10,000 फीट से अधिक की दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, अटल सुरंग, रोहतांग को यातायात के लिए खोल दिया गया, जिससे उत्तरी सीमाओं को हर मौसम में जोड़ा जा सके। मॉड्यूलर ब्रिज की लागत और आयात निर्भरता को कम करने के लिए, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के सहयोग से पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए मॉड्यूलर ब्रिज को डिजाइन किया गया था।

2020 में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की गतिविधियाँ

जोजिला दर्रा, जो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है, 12 अप्रैल, 2020 को खुलेगा। धारचूला और लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क मई 2020 में खोली गई थी। जुलाई 2020 में, छह डीआरडीओ–निर्मित पुल बनाए गए थे। जम्मू और कश्मीर में और उसके आसपास उद्घाटन किया गया।

रक्षा को मजबूत करना, भारतीय सेना में मारक क्षमता बढ़ाना

सरकार ने भारतीय वायु सेना में हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

- **आईएनएस विक्रांतः** अपने स्वयं के युद्ध समूह से सुसज्जित एक तैरती हवाई पट्टी के रूप में डिज़ाइन किया गया, आईएनएस विक्रांत को 13 साल की यात्रा के साथ 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि अब यह अपने स्वयं के विमान वाहक का उत्पादन करने में सक्षम देशों के प्रतिबंधित समूह में शामिल हो गया है।

- **C–295 फैक्ट्री की स्थापनाः** 2022 में C–295 परिवहन विमान बनाने के लिए एक प्लांट की आधारशिला रखी गई। गुजरात के वडोदरा में यह देश की पहली निजी क्षेत्र की परियोजना है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, स्पेन इस परियोजना पर सहयोग कर रहे हैं।

- **राफेल विमान शामिलः** रूस से सुखोई विमानों के आयात के बाद, 23 वर्षों में अत्याधुनिक विमानों का पहला महत्वपूर्ण IAF अधिग्रहण। 36 विमानों का पूरा बेड़ा 2022 के अंत तक भारत को सौंप दिया जाएगा।

- **एलसीएच प्रचंडः** एचएएल द्वारा विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) प्रचंड को औपचारिक रूप से 3 अक्टूबर, 2022 को जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया।

- **AK–203 राइफल्सः** भारत और रूस ने दिसंबर 2021 में यूपी के अमेठी क्षेत्र में कोरवा आयुध फैक्ट्री के माध्यम से 6,01,247 AK–203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए 5,124 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंडो–रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के हिस्से के रूप में भारत में छह लाख से अधिक राइफलें निर्मित की जाएंगी। इस समझौते में संपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रावधान शामिल है। उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित एक प्लांट में AK–203 राइफल्स की असेम्बलिंग शुरू हो गई है।

नवाचार और वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सुधारः 2020 में, 35 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों की विशेषता वाली पांच प्रयोगशालाएँ लॉन्च की गईं; असममित युद्ध प्रौद्योगिकी कोलकाता में स्थित है, जबकि संज्ञानात्मक सेंसर प्रौद्योगिकी चेन्नई में स्थित है, स्मार्ट मटेरियल्स हैदराबाद में स्थित है, और क्वांटम टेक्नोलॉजी मुंबई में स्थित है।

- अगस्त 2020 में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने उद्योग के लिए डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए 108 प्रणालियों और उप–प्रणालियों को नामांकित किया।

- **सशस्त्र बलों में स्त्री शक्तिः** भारतीय सेना ने एसएससी महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन के लिए दस धाराओं की पेशकश की। भारतीय नौसेना की महिला पायलटों ने एसएससी महिला अधिकारियों के लिए पहली बार आयोग में भाग लिया। एनडीए और सभी सैनिक स्कूलों में भाग लेने वाली लड़कियों को 2020–21 शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाली महिला छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया है

- **रक्षा भूमि प्रबंधन में सुधारः** भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) ने 17.9 लाख एकड़ रक्षा भूमि की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग के निर्माण में सहायता की। अक्टूबर 2020 में, रक्षा मंत्रालय ने भूमि हस्तांतरण के अनुरोधों की दक्षता और समयबद्धता में सुधार के लिए एक पूरी तरह से डिजिटलीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली का अनावरण किया। जुलाई 2020 में, एक नई नीति की घोषणा की गई थी जो निर्दिष्ट करती है कि रक्षा भूमि पर निर्मित सुरंगों के लिए कोई लीजिंग शुल्क नहीं देना होगा। अक्टूबर 2020 में, सड़कों, मोटरवे, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता जैसी विकास परियोजनाओं के लिए रक्षा भूमि के उपयोग को सक्षम करने के लिए एक नई नीति रूपरेखा स्थापित की गई थी।

छावनी प्रबंधन में सुधार–डिजिटलीकरण

- **बेहतर पहुंच, दक्षता और संगठनः** छावनी संशोधन अधिनियम तैयार किया गया था और सार्वजनिक चर्चा के लिए खुला था। 1 अप्रैल, 2020 को सभी 62 छावनियों को प्रोद्भवन–आधारित लेखांकन (ऐतिहासिक नकदी–आधारित लेखांकन के बजाय) में बदल दिया गया। छावनी बोर्ड के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिक अधिकार दिए गए, और तीन नई समितियों का गठन किया गया यानी वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण।

- **स्थानीय पहुंच का विस्तार करने के लिए अभूतपूर्व एनसीसी सुधारः** सीमा और तटीय क्षेत्रों में 1078 स्कूलों/कॉलेजों में नामांकन नवंबर 2020 में शुरू होगा। मई 2020 से शुरू होकर, एनसीसी कैडेटों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रोजगार के लिए पहली प्राथमिकता दी जाएगी। एनसीसी कैडेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। राष्ट्रों की संख्या 10 से बढ़कर 15 हो गयी। पहला एनसीसी पूर्व छात्र समूह नवंबर 2020 में गठित किया गया था।

- **रणनीतिक सोच तक अनुसंधान–केंद्रित पहुंच स्थापित करनाः** रणनीतिक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए थिंक टैंक/अनुसंधान केंद्रों से संपर्क करना; राष्ट्रीय सुरक्षा में राष्ट्रपति की उत्कृष्टता पीठ की स्थापना 11 नवंबर, 2020 को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में की गई थी; अंतर्निहित कारणों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस–आधारित समाधान बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के बीच अगस्त 2020 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

रक्षा मंत्रालय के विरुद्ध शिकायतें/शिकायतें, ऑफसेट सुधारः सितंबर 2020 में एक नई ऑफसेट नीति को मंजूरी दी गई। भारत की ऑफसेट नीति के तहत विदेशी विक्रेताओं को 200 करोड़ से ऊपर के सभी पूंजीगत अधिग्रहणों में स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए खरीद मूल्य का कम से कम 30: देश में निवेश करने की आवश्यकता होती है। 36 लड़ाकू विमानों के लिए 59,000 करोड़ के राफेल समझौते के मामले में यह 50 प्रतिशत था।

ऑफसेट सुधारः सितंबर 2020 में एक नई ऑफसेट नीति को मंजूरी दी गई। भारत की ऑफसेट नीति के तहत विदेशी विक्रेताओं को 200 करोड़ से ऊपर के सभी पूंजीगत अधिग्रहणों में स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए खरीद मूल्य का कम से कम 30: देश में निवेश करने की आवश्यकता होती है। 36 लड़ाकू विमानों के लिए 59,000 करोड़ के राफेल समझौते के मामले में यह 50 प्रतिशत था। विक्रेता अपने भारतीय ऑफसेट पार्टनर (आईओपी) का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

मजबूत रक्षा निर्यात विकास के लिए एक नई अंतर्दृष्टिः रक्षा क्षेत्र की निर्यात वृद्धि 2016 और 2020 के बीच आठ गुना बढ़ गई। निर्यात अब 84 देशों तक पहुंच गया है। इसके पीछे व्यावसायिक क्षेत्र की व्यस्तता प्राथमिक कारणों में से एक थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने अपनी 2019 हथियार निर्यातक सूची में भारत को 23वां स्थान दिया है।

चिकित्सा क्षमता का उपयोग करनाः सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (एएफएमएस) द्वारा सीओवीआईडी–19 के खिलाफ लड़ाई को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया गया। इसमें बिस्तरों, संगरोध केंद्रों और चिकित्सा इकाइयों की स्थापना शामिल है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, 20 एएफएमएस अस्पताल 21 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहयोग करेंगे। सशस्त्र बल चिकित्सा अस्पतालों के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल उम्मीदवार उपलब्ध हैं। एएफएमएस डॉक्टर पार्टनर मेडिकल स्कूलों में पढ़ाएंगे।

रक्षा औद्योगिक गलियारे (डीआईसी): चूंकि भारत शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वालों में से एक है और एक उभरता हुआ विनिर्माण केंद्र है; डीआईसीएस रक्षा क्षेत्र की वृद्धि का समर्थन करेगा, विनिर्माण क्षमता बढ़ाएगा, 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देगा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, आयात कम करेगा और निर्यात बढ़ाएगा।

यह भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने के लिए यूपी और तमिलनाडु में किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यूपी डीआईसी की स्थापना यूपी एक्सप्रेस वेज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी फैसिलिटीज द्वारा की जाएगी, और इसमें छह नोड होंगे, यानी, अलीगंज, कानपुर, चित्रकोट, झाँसी, लखनऊ और आगरा। तमिलनाडु डीआईसी की स्थापना तमिलनाडु सरकार द्वारा की जाएगी, और इसमें पांच नोड होंगे, यानी, चेन्नई, कोयंबटूर, होसुर, सलेम और तिरुचिरापल्ली।

आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) का निगमीकरणः देश के इकतालीस उद्योगों को सात नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) में समेकित किया जाएगा। इन नवगठित संगठनों पर पूर्ण स्वामित्व सरकार का होगा।

गोला–बारूद और विस्फोटक समूहः बड़ी निर्यात क्षमता वाले विभिन्न कैलिबर के गोला–बारूद के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।

वाहन समूहः टैंक, ट्रॉल्स, माइन–प्रोटेक्टेड वाहन (एमपीवी), और बख्तरबंद कार्मिक वाहक जैसे लड़ाकू वाहनों का निर्माण करना।

हथियार और उपकरण समूहः छोटे निर्माण के लिए,मध्यम और बड़े कैलिबर सुरक्षा आग्नेयास्त्र।

ट्रूप्स कम्फर्ट ग्रुपः सैनिकों के लिए वर्दी और विशेष गियर का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त सहायक समूह, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स समूह और पैराशूट समूह अन्य तीन हैं।

ओएफबी के निगमीकरण से आयुध को मजबूती मिलेगी। आपूर्तिकर्ता की स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता। इससे रक्षा निर्माताओं की उत्पादकता और लाभप्रदता के साथ–साथ उनकी उत्पाद विशेषज्ञता, प्रतिस्पर्धात्मकता, गुणवत्ता और लागत–दक्षता में वृद्धि होगी।

इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स (आईटीसी): की अवधारणा के निष्कर्षों में थिएटर कमांड का प्रस्ताव रखा गया था।

थिएटर कमांड का प्रस्ताव सैन्य सुधार समिति के निष्कर्षों में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीबी शेकतकर ने की थी। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए तीनों सेवाओं के संसाधनों को एक ही कमांडर के अधीन एकत्रित किया जाएगा।

वर्तमान में, 19 कमांड हैं, 14 भौगोलिक कमांड, तीन कार्यात्मक कमांड और दो संयुक्त कमांडः स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (एसएफसी) और अंडमान और निकोबार कमांड (एएनसी)। वर्तमान अवधारणा के अनुसार, पाँच थिएटर कमांड होंगेः उत्तरी लैंड थिएटर (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और मध्य क्षेत्र सहित) चीन पर केंद्रित; वेस्टर्न लैंड थिएटर (पाकिस्तान पर केंद्रित); पूर्वी भूमि रंगमंच; मैरीटाइम थिएटर कमांड (पूर्वी और पश्चिमी नौसैनिक कमांड का संयोजन, साथ ही सेना और वायु सेना के तत्व); वायु रक्षा कमान

भविष्यगत सुधार एवं सम्भावनाएँ

इस बदले हुए भू–राजनीतिक परिदृश्य में, रक्षा सुधार होंगे जो भारत के क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति बनने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा।

मेक इन इंडिया परियोजना और आत्मनिर्भर भारत योजना रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी और साथ ही भारत को विश्वव्यापी विनिर्माण केंद्र बनाएगी। रक्षा अनुबंध अब 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण' प्रावधान के अधीन हैं। इससे निर्यात बढ़ने के साथ–साथ आयात में उत्तरोत्तर कटौती होगी। देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार पैदा करेगा। रक्षा सुधारों से नागरिक–सैन्य संबंधों के साथ–साथ क्षेत्र की प्रभावकारिता और जवाबदेही भी मजबूत होगी। इंटरसर्विसेज ऑर्गनाइजेशन कानून त्रि–सेवा संपर्क और सहयोग में सुधार करेगा। अंतर–सेवा पोस्टिंग से सैन्य कमांडरों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी प्रगति के साथ चलने वाले रक्षा सुधार यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सशस्त्र बल भविष्य के लिए तैयार हैं। परिणामस्वरूप, निकट भविष्य में, भारत वैश्विक शक्ति गतिशीलता में एक 'संतुलक' के रूप में काम करेगा।

लेकिन वर्तमान सुरक्षा ढांचे में सुधार एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए बहुत अधिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। पिछले प्रशासन के शासनकाल के दौरान, विभिन्न सुधार समितियों के प्रस्तावों को अधर में लटका दिया गया था, और जिस दर से सुधार हुए थे, उसका राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर असर पड़ा, लेकिन इस सम्बन्ध में मोदी सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता और भारत को विश्वव्यापी विनिर्माण केंद्र बनाने का उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ प्रमुख चुनौतियाँ रक्षा सुधार में बाधाएँ हैं।

इस सम्बन्ध में मेरी चिंताएँ निम्नलिखित हैंः

- **संस्थागत अक्षमता** – संस्थागत अक्षमता और क्षमता की कमी के परिणामस्वरूप नीति विफलता हो सकती है। जब संस्थाएं अक्षम होती हैं, तो वे प्रभावी नीतियां विकसित करने में असमर्थ हो सकती हैं। जब संस्थाओं के पास क्षमता की कमी होती है, तो वे नीतियां लागू करने में असमर्थ हो सकती हैं। बुनियादी ढांचा एक देश की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह सैनिकों को तैनात करने, हथियारों और उपकरणों को ले जाने, और आपूर्ति और सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है। जब बुनियादी ढांचा अपर्याप्त या अक्षम होता है, तो यह रक्षात्मक लड़ाई और रसद स्थापना को बाधित कर सकता है। यह विलम्ब का एक बड़ा कारण है क्योंकि यह सैनिकों को तैनात करने और आपूर्ति और सेवाएं प्रदान करने में देरी कर सकता है। इससे सैनिकों को नुकसान हो सकता है और रक्षात्मक लड़ाई को कमजोर कर सकता है।
- **विवाद निपटान निकाय का अभाव** – इसके परिणामस्वरूप,एक स्थायी मध्यस्थता निकाय बनाना महत्वपूर्ण है जो विवादों का शीघ्रता से समाधान कर सके। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अधिग्रहण संगठन DARPA (डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी) एक स्थायी मध्यस्थता निकाय रखता है जो ऐसे मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करता है और जिसका फैसला निश्चित होता है। बुनियादी ढाँचें की कमी से लॉजिस्टिक लागत बढ़ जाती है जिससे देश की किफायती मूल्य निर्धारण और उत्पादकता कम हो जाती है।
- **भूमि कब्जे की बाधाएँ** – नए प्रवेशकों को सीमित करती हैं।
- **रक्षा उत्पादन नीति सम्बन्धी दुविधा** – अर्थात डीपीपी के तहत ऑफसेट मानदंड नहीं है।

उपरोक्त बाधाओं को यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिए, अन्यथा हम तकनीकी रूप से परिष्कृत देशों से पीछे रह जायेंगे।

इन समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव निम्न हैं –

- विवादों के समाधान के लिए एक स्थायी मध्यस्थता निकाय बनाना।
- स्वदेशी सैन्य उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक व्यवस्थित और प्रभावकारी प्रौद्योगिकी और मानव संपत्ति के समावेश के लिए गैर–सार्वजनिक क्षेत्र का उत्थान महत्वपूर्ण है।
- लक्ष्य निर्यात क्षमता हासिल करना होना चाहिए यानी हथियार हमारे सशस्त्र बलों की सेवा में होने चाहिए।
- स्थानीय स्तर पर 'चिप' बनाने और उत्पादन करने के लिए साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियोजित किया जाना चाहिए।
- डीआरडीओ को मौद्रिक और कार्यकारी स्वतंत्रता देने से इसका विश्वास और अधिकार बढ़ेगा।
- रक्षा उत्पादन विभाग में कर्मियों की निरंतरता के लिए, औपचारिक प्रशिक्षण और कार्यालय की विस्तारित शर्तों पर विचार किया जाना चाहिए।
- निवेशित कंपनियों को स्वयं संगठित होना चाहिए वे उत्पाद डिजाइन और विकास में आत्मनिर्भर हैं और इसका लाभ रक्षा उत्पादन में लेने का प्रयास होना चाहिए।
- तीनों सेवाओं के बीच इन–हाउस डिज़ाइन में सुधार करना। जैसे नौसेना के नेवल डिज़ाइन ब्यूरो ने स्वदेशीकरण में प्रगति की और डीआरडीओ पर निर्भर नहीं रहा।
- रक्षा निर्माताओं के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला लागत कम किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत के रक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, भारत को आत्मनिर्भर, वैश्विक और आधुनिक रक्षा बल बनाने में मदद करेंगे। सशस्त्र बलों के बीच समन्वय और नागरिक–सैन्य एकीकरण को सुगम बनाने हेतु सीडीएस की नियुक्ति, रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले 101 रक्षा मदों के आयात पर प्रतिबंध, रक्षा खरीद में पारदर्शिता और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में प्रक्रियागत तेजी सुनिश्चित करना, रक्षा निर्यात में वृद्धि करने और भारत को रक्षा उपकरण निर्यातक देशों की सूची में शामिल करने वाली रक्षा निर्यात प्रोत्साहन योजना, युवा वैज्ञानिकों को अवसर देने और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ाने वाले रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सुधार, रक्षा सेवाओं को डिजिटल रूपांतरण द्वारा आधुनिक और कुशल बनाने वाली डिजिटल रक्षा योजना, और भारत की सुरक्षा और सामरिक लाभ को बढ़ाने हेतु सीमा पर बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने वाले सीमा ढाँचा योजना जैसे कदम निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही भारत सरकार को सम्बन्धित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसे दूर करने हेतु भी तत्परता दिखानी होगी। युवाओं को इस दिशा में उचित प्रशिक्षण और प्रतिनिधित्व देने का प्रयास होना चाहिए। भारतीय सुरक्षा तन्त्र के आत्मनिर्भरता की दिशा सकारात्मक है और आशा है निकट भविष्य में भारत पूर्व से अधिक सुरक्षित होगा जो न केवल स्वयं की अपितु दक्षिण एशिया में भी सुरक्षा सहयोग का प्रतिनिधित्व कर सकेगा।

सन्दर्भ

1. अब्राहम, टी.के., रीथिंकिंग इन्डियन डिफेन्सरू अ स्ट्रेटेजिक रीअसेसमेंट, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 2019
2. चन्द्रशेखर, के., इण्डियाज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशनरू चलेंजेज एण्ड अपोर्चुनिटीज, राउटलेज, 2021
3. घोषाल, बी., द फ्यूचर ऑफ़ मिलिट्री पॉवर इन इण्डिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2015
4. गुप्ता, एस., रीफार्मिंग द इन्डियन डिफेन्स सेक्टररू इसूज एण्ड चौलेंजेज, केडब्ल्यू पब्लिशर्स प्रा. लिमिटेड, 2018
5. झा, ए., इण्डियाज डिफेन्स रिफार्म्सरू अ क्रिटिकल एनालिसिस, पेंटागन प्रेस, 2020
6. कोहली, यू. एस., मिलिट्री पॉवर एण्ड नेशनल सिक्यूरिटी इन इण्डिया, सेज पब्लिकेशंस प्रा. लिमिटेड, 2017
7. माथुर, आर. सी., रीथिंकिंग इन्डियन डिफेन्स पॉलिसीरू अ स्ट्रेटेजिक विजन, स्प्रिंगर नेचर, 2019
8. नायडू, जी. वी. सी., इन्डियन डिफेन्स रिफार्म्सरू नीड फॉर अ पैराडाइम शिफ्ट, विज बुक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, 2016
9. सिंह, आर. एस., इण्डियाज डिफेन्स चौलेंजेज,एण्ड रेस्पोंसेज, लांसर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2022
10. वैद, यू., इण्डियाज स्ट्रेटेजिक चौलेंजेज,एण्ड रेस्पोंसेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2018